



## स्वास्थ्य मंत्री की फुटेज लीक होने की जांच कराएगा ब्रिटेन, सहयोगी को किस करने का वीडियो हुआ था वायरल

लंदन. ब्रिटेन की सरकार ने रविवार को कहा कि वह मैट हैनकाक की वीडियो फुटेज लीक होने के मामले की जांच कराएगी, जिसके चलते उनको स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था। स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा विभाग इस बात की जांच करेगा कि हैनकाक द्वारा अपनी सहयोगी को किस करने का वीडियो दफ्तर के अंदर कैसे तैयार किया गया।

हैनकाक के पूर्व कार्यालय में कैमरे की मौजूदगी को लेकर जांच की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस फुटेज का सुरक्षा के लिहाज से भी आकलन किया जा रहा है। उत्तरी आयरलैंड मामलों के मंत्री ब्रैंडन लेंसिस ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग वर्ष समझने का प्रयास करेगा कि यह घटना कैसे थी? हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि सरकारी इमारत के भीतर कैसे कोई व्यक्ति रिकार्डिंग करने में कामयाब हो गया। इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि हमें इससे किस तरह नियन्त्रित करना चाहिए।

बायांते चलते कि अपनी एक करीबी महिला सहायक को किस करने पर स्वास्थ्य मंत्री हैनकाक ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया था। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री के इस व्यवहार को कोरोना लाकडाउन नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके चलते उनसे व्याप्रत्र की मांग की जा रही थी।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन को लिखे पत्र में हैनकाक ने कहा कि सरकार उन लोगों की ज़रूरी है, जिन्होंने इस महामारी के दौरान इतना बल्लिदान दिया है। इमानदारी से कहें तो हमें उन्हें निराश किया है। शारारिक दूरी को लेकर सरकार के दिशा-निर्देशों को तोड़ने के लिए उन्होंने फिर से मापी मांगी है। टिक्टटर पर पोस्ट किए एक वीडियो में हैनकाक ने कहा, मैं स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा मंत्री के पद से व्याप्रत्र देने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ दखल रहा हूँ।

**दशकों से हैं तालिबान से पाकिस्तान की आईएसआई और सेना के संबंध, अमेरिका के पूर्व एनएसए का बड़ा बयान**



वाशिंगटन (रॉयटर्स). अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा है कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के लिए केवल पाकिस्तान ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। खामा प्रेस के मुताबिक उन्होंने ये बयान अमेरिका के वायस ऑफ अमेरिका को दिए एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। उन्होंने भी कहा कि जब से अमेरिका ने तालिबान की वापसी के बिलाक भी की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहां तक कहा तक कहा कि पाकिस्तान की इंटर्लैंजेंसी और उनका इंटरनल सर्किल दशकों से तालिबान के संपर्क में है।

इस इंटरव्यू के दौरान बोल्टन ने ये भी कहा कि जब से अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापस जाने की बात की है और इसकी शुरुआत की है तब से तालिबान लगातार देश में अपने पांच फैला रहा है। कई जिलों की ओपने कब्जे में कर चुका है। बोल्टन ने तालिबान को एक सुरक्षित जगह मुहूर्हा कराने पर पाकिस्तान की बिंचाई भी की है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में यहां तक कहा तक कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ही नहीं अफगानिस्तान फोर्स के बिलाक भी काम करने में व्यक्ति है। अफगान फोर्स के ऊपर हमला करने में भी उसकी भूमिका है।

बोल्टन ने इस इंटरव्यू में पाकिस्तान को आगाह किया है कि यदि अफगानिस्तान में तालिबान ने सलता हाथी ली तो वो पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खाता बन जाएगा। ऐसी सूत्र में पाकिस्तान की सरकार पर आंतकी संगठनों की संख्या बढ़ने का जबरदस्त दबाव होगा। बोल्टन ने इस इंटरव्यू में साफ कहा कि वो व्यवहार को लेकर काफी चिंतित हैं। अमेरिका के व्यापर एनएसए का ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के अफगानिस्तान से बाहर निकलने की समय सीमा लगातार कम हो रही है।

## जो ब्रिटेन का एक्शन, सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया पर अमेरिका ने किए हवाई हमले

विदेश. अमेरिका ने ईराक और सीरिया के बीच सीमा के निकट ईरान समर्थित मिलिशिया समूहों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले ठिकानों को निशाना बनाकर रविवार को हवाई हमले किए और उन्हें तबाह कर दिया।

पैंटांग के प्रेस सचिव जॉन किंबी ने बताया कि ये मिलिशिया समूह ईराक में अमेरिकी वालों के खिलाफ मानवरहित यथा से हमले करने के लिए इन ठिकानों का इस्तेमाल कर रहे।

किंबी ने बताया कि अमेरिकी सेना ने सीरिया में दो और ईराक में एक यानी कुल तीन ठिकानों पर हमले किए।

इन ठिकानों से मिलिशिया समूह अपने अधियान चलाते थे और यहां हथियार भी रखते थे। बताया जा रहा है कि इस मिलिशिया गुप्त ने ईराक में अमेरिकी दुतावास पर रोकेट हमला किया था। रोकेट हमले में अमेरिकी सैनिक घायल हो गए थे और एक थे केंद्रकर



आवश्यक, उचित और सोच-समझकर कार्रवाई की।

ये हमले राष्ट्रपति जो ब्रिटेन के निर्देश पर किए गए हैं। ये पद संभालने के पांच महीनों में दूसरी बार उन्होंने ईरान समर्थित मिलिशिया के खिलाफ जवाबी हमले का आदेश दिया है। ब्रिटेन ने आखिरी बार फरवरी में उस समय ईराक में रोकेट हमलों के जवाब में सीरिया में सीमित हमलों का आदेश दिया था। यह हमले अमेरिकी कर्मियों की खातिर एक स्पष्ट संदेश भेजने के लिए।

दिखाते हैं।

ब्रिटेन और व्हाइट हाउस ने रविवार को हुए हमलों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि ईराक में अमेरिकी कर्मियों और सुविधाओं के खिलाफ ड्रोन हमलों में ईरान का हाथ है, जहां अमेरिकी सेना बगदाद को इस्लामिक स्टेट के अवशेषों से निपटने में मदद कर रही है।

**ब्रिटेन: कोरोना में सहयोगी को किस करने पर बुरे फँसे मंत्री ने दिया इस्तीफा**

ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री मैट हैनकॉक ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी एक नजदीकी सहयोगी किस कर कोविड-19 नियमों को तोड़ा था जिसके बाद से उन पर त्यागात्र देने का दबाव था। हैनकॉक ने किस करने की बात स्वीकार भी की थी।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉनसन को लिखे पत्र में हैनकॉक ने कहा कि अपनी एक करीबी महिला सहायक को किस करने पर स्वास्थ्य मंत्री हैनकाक ने इस्तीफा दे दिया था। दरअसल, स्वास्थ्य मंत्री के इस व्यवहार को कोरोना लाकडाउन नियमों का उल्लंघन माना गया। इसके चलते उनसे व्याप्रत्र की मांग की जा रही थी।

## कनाडा : ब्रिटिश कोलंबिया में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल, टूटा कई सालों का रिकॉर्ड

तीरीय शहर वैंकूवर में रविवार को दोपहर में तापमान 31 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इस दौरान कई लोग समुद्र तट की ओर चले गए हालांकि भीषण गर्मी के कारण भीड़ गर्मी से थोड़ी कम ही दिखाई दी।

वैंकूवर दक्षिणी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदरूनी हिस्से में स्थित लिटन (Lytton) के गांव में रविवार को तापमान बढ़कर 46.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इसके साथ ही 1937 का वह रिकॉर्ड टूट गया है जब सक्रेन चैवान में 45 डिग्री सेल्सियस



किए गए, हालांकि भीषण गर्मी में भीड़ गर्मी से थोड़ी कम ही दिखाई दी। यहां एक निवासी नाताली मोजर ने बताया कि यहां कई लोग आस-पास के पांचों में छाया की तलाश कर रहे थे। मोजर ने कहा कि वह विशेष रूप से गर्म मौसम के दौरान पूल का आनंद लेने के लिए आप तैर पर एक स्थानीय होटल में रहती थी, लेकिन महामारी प्रतिक्रियों से यह विकल्प बाधित हो गया है।

अमेरिका में बेतहाशा गर्मी अमेरिकी में इन दिनों प्रचंड गर्मी से लोगों की हालत खुशी हो गई है।

यहां पर कई जगहों पर तापमान में रिकॉर्ड तैर देखी गई है। मौसम गर्मी पूर्णुमान लगाने वाले बैतानिकों का कहना है कि एक्सेप्टेस्ट कोशिश कर रहे हैं। जिस इमारत में बिस्कोट बुड़ा, उसमें एक फास्टफूड की दुकान थी।

## Blast in Dhaka: बांग्लादेश की राजधानी में विस्फोट, सात की मौत, 50 घायल अस्पताल में भर्ती, 10 की हालत गंभीर

Blast in Dhaka तुकान में गैस पाइप लाइन या गैस लिंगों के कारण हो सकती है। बाका के एक टीवी चैनल के गुरुवारिक रीपी 50 घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

दक्षा. बांग्लादेश की राजधानी ढाका में रविवार शाम हुए एक विस्फोट में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। विस्फोट के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

विस्फोट इतना तेज था कि सात इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

अविनाशमन विभाग के एक

अधिकारी फैसलुर रहमान ने

बताया कि विस्फोट ढाका के

मोबाइल इलाके के एक इमारत

में हुआ। विस्फोट के लिए आपसाम की करीब सात इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं।

जिस इमारत में बिस्फोट हुआ है, उसमें एक

# दिल्ली में 5000 हेल्थ असिस्टेंट तैयार करने की हुई शुरूआत

नई दिल्ली, (एजेंसी)। दिल्ली सरकार कोरोना की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों को महेनजर रखते हुए युद्धस्मरण पर काम कर रही है। इसी दिशा में गुरु गोविंद सिंह आईपी विश्वविद्यालय द्वारा 5000 कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट को ट्रेनिंग दी जाएगी। सोमवार से इस कोर्स का पहला बैच शुरू हो चुका है। ये हेल्थ असिस्टेंट डॉक्टरों और नर्स के असिस्टेंट के रूप में काम करेंगे। सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस प्रोग्राम का आधिकारिक लांच किया।

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम का पहला बैच 28 जून से शुरू हो गया है जिसमें 500 ट्रेनीज को कई तरह के काम जैसे पैरामेडिक, लाइफ सेविंग, फर्स्ट एड, हाम केरार की ट्रेनिंग दी जाएगी। इन्हें ऑक्सीजन नापने, ब्लड प्रेशर सापेन, इंजेक्शन लगाने, कैथेटर, सैंपल कलेक्शन, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क लगाने जैसे काम सिखाए जाएंगे। 14 दिन की इस ट्रेनिंग को 2 चरणों में बांटा जाएगा। पहले चरण में



ट्रेनीज को 1 सप्ताह तक डेमोस्टेशन क्लास के जरिए बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और उसके अगले सप्ताह अस्पतालों में असिस्टेंट के रूप में काम सिखाया जाएगा।

ट्रेनीज को दिल्ली के 9 बड़े अस्पतालों दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, राजीव गांधी सुपर सेशनलिटी हॉस्पिटल, चाचा नेहरू बाल

# संपादकीय

# हम कानून से कब तक दूर भागेंगे

देश की सर्वोच्च अदालत राजद्रोह कानून की फिर से व्याख्या करने जा रही है। यह खासा महत्वपूर्ण है कि औपनिवेशिक युग के जिस कानून को खुद बिटेन ने अपने यहां निरस्त कर दिया, उसको अब तक भारत में किसी भी सरकार ने रह नहीं किया, उल्लेख में से पत्तेक ने इसका इस्तेमाल ही किया। जबकि, राजद्रोह कानून देश के उन तमाम कानूनों का शीर्षस्थ सिरा है, जिस पर नए सामाजिक नजरिए से विश्लेषण की जरूरत है। हममें से ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि कानून का पालन करने वाले हम अच्छे नागरिक हैं। कानून सर्वोच्च सार्वजनिक और निजी भलाई को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। हम उन सभी कानूनों के पालन का प्रयास करते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं। ऐसा करने से हम एक ऐसे समाज का हिस्सा बन जाते हैं, जो कानूनों द्वारा न्यायपूर्वक शासित होता है। हम जेल के जन-जीवन की नहीं सचेत, क्योंकि हम मानते हैं कि हम ऐसा कुछ करने की कल्पना भी नहीं कर सकते, जो हमें सलाखों के पांछे पहुंचा दे। और अगर गलती से हम फंस गए, तो निश्चय ही किसी दूसरे रास्ते से बच निकलेंगे! क्योंकि, जेल हमारे लिए नहीं, दूसरों के लिए है। क्या इन सभी धारणाओं पर फिर से विचार करने का समय आ गया है? सतहीं तौर पर देखें, तो हमारे कई कानूनों में अपराध के हिसाब से सजा या जेल का प्रावधान नहीं है। कई कानून तो लोक-व्यवस्था की जिम्मेदारी राष्ट्र और उसके तंत्र के बजाय नागरिकों और उनके व्यवहार पर डाल देते हैं। दुखद है, ऐसे कई कानून बिना विधायी बहस के पारित हुए हैं। जैसे, क्या आपको पता है कि पालतू कुते को यदि आप ठीक से नहीं घुमाते, तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है? इसमें अधिकतम तीन महीने की सजा मिल सकती है। क्या आपको जानकारी है कि प्रतिबंधित धरों से पतंग उड़ान पर दो साल की सजा हो सकती है? बिना बीमा वाली गाड़ी चलाने पर भी आप तीन महीने के लिए जेल जा सकते हैं? फिर भी, अधिकांश भारतीय नागरिक कानून-नियमण या आपराधिक न्याय के मसलों पर सजीदीया नहीं दिखाते। दशकों, यहां तक कि सदियों से कायम कठोर और बेरहम कानूनों के अलावा कुछ नए नियम-कानून भी हैं, जो शासन को व्यापक अधिकार देते हैं। हां, सुखद यह है कि अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के बहाने कुछ कानूनों पर गंभीर सार्वजनिक बहस हुई है। ऐसी ही एक जीत आईटी ऐक्ट की धारा 6ए को असांविधानिक करार देने से हमें मिली थी। हालांकि, अभिव्यक्ति पर चोट करते ऐसे कई अन्य कानून अब भी मौजूद हैं, लेकिन सोशल मीडिया के व्यापक इस्तेमाल के कारण लोगों को ये कानून संभवतः बहुत ज्यादा असरंदाज होते नहीं महसूस होते। एक अन्य ताजा उदाहरण देखिए। सरकार ने महामारी के समुचित प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 लागू किया। लेकिन यदि इसे सख्ती से लागू किया जाता, तो इसके कुछ प्रावधान शायद लाखों लोगों को हवालात की सैर करा देते। जैसे, कोविड-19 से जुड़ी फर्जी खबरों को फैलाना। इसमें वाट्सएप मैसेज भी शामिल है, जो बाद में यदि गलत साबित हो जाए, तो आपको एक साल तक की जेल हो सकती है। इसी तरह, बिना किसी ठोस वजह से मासक न पहनने पर भी एक साल तक की सजा तय है। जाहिर है, इनमें से कुछ कानूनों को लागू करना संभव नहीं है या फिर ये उन अधिकारियों की नजरों से दूर होंगे, जिनके पास गिरफ्तार करने का वैधानिक अधिकार है।

करने का विचानक आधिकार है। मगर यहां मसला इन कानूनों की मौजूदी का है। और, परिस्थितियां कभी भी इस कदर बदल सकती हैं कि कोई व्यक्ति अनजाने में की गई गलती के लिए भी कहीं बड़ी मुश्किलें झेल सकता है। यहां मैंने जिन कानूनों का जिक्र किया है, उन सभी में गिरफ्तारी का प्रावधान है। तो क्या इस तरह के असंगत दंडनीय कानून बने रहें चाहिए? क्या पारित होने से पहले इनकी बेहतर ढंग से व्याख्या नहीं होनी चाहिए? क्या ये उस उद्देश्य और मंशा (अमूमन लोक-व्यवस्था और सुक्ष्मा) को पूरा करते हैं, जिनके लिए इनको बनाया जाता है? हमारे पास इन्हें सुबूत नहीं हैं, जो सावित कर सकें कि कहीं सजा से अपराध कम होते हैं। शोध तो यही बताते हैं कि कठोर कारावास का अंजाम आमतौर पर अपराधी द्वारा फिर से कहीं अधिक संगीन जुर्म किए जाने के रूप में सामने आता है। दूसरी ओर, संबल देने वाली न्याय-प्रणालियों के सुखद परिणाम दिख रहे हैं, जिनमें खुली जेल की व्यवस्था भी एक है। क्या हम इस तरह के सुबूतों का इस्तेमाल अपनी दंडात्मक न्याय-प्रणाली को कहीं अधिक न्यायपूर्ण, मानवीय और प्रभावशाली बनाने के लिए कर सकते हैं? अब तक हम, यानी अभिजात वर्ग कानून-निर्माण और जेल सुधार पर गंभीर सार्वजनिक बहसों से बचते रहे हैं। चरणबद्ध लॉकडाउन ने हमसे से कई लोगों को यह एहसास दिलाया होगा कि जेल की चारदीवारी में बद द्वेष वाले आखिर किस पीड़ि से ऊरजते होंगे। लिहाजा, क्या हमारा समाज अब उन कानूनों पर गंभीर बहस कर सकता है, जिनसे किसी व्यक्ति को बहुत आसानी से अपराधी ठहरा दिया जाता है? और इसके बाद, हम कहीं अधिक व्यापक मसले पर चर्चा कर सकते हैं, जिनमें हट से अधिक भरी जेलों (जिनमें 70 फीसदी कैदी संभवतः निर्दोष विचाराधीन हैं) में मानवाधिकारों के उल्लंघन सहित आपराधिक न्याय का मसला महत्वपूर्ण है। सर्वोच्च न्यायालय ने अब राष्ट्रद्वारा कानून को विरास के केंद्र में ला दिया है, जबकि महामारी ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को। इसलिए यह वक्त सांसदों और विधायिकों द्वारा गहन चर्चा करने का है कि कैसे एक बेहतर कानून एक बेहतर समाज का निर्माण सुनिश्चित कर सकता है। आईटी एक्ट की धारा 66ए को रद्द करने में इसी तरह के विरास ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाई थी। रही बात भारत के कुलीन वर्ग की, तो वह हर आम सार्वजनिक सेवा से खुद को अलग रखता है, फिर चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन या बिजली। प्रदूषण और महामारी ने यह कड़वी सच्चाई बताई है कि दूषित हवा और खतरनाक कीटाणुओं से हम खुद को अलग नहीं कर सकते। बुरे कानून भी अपवाद नहीं हैं। हम इनसे कर्त्ता नहीं भाग सकते।

जहां पर वन संरक्षण कानून लागू होता है, वहां पर सरकार से संबंधित विकास कार्य ही केवल किए जा सकते हैं। ऐसे में अरावली के पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए हमें इसके पर्याप्त संरक्षण के पुख्ता उपायों को अमल में लाना होगा। रेगिस्तान की रेत को रोकने के अलावा अरावली मिट्टी के क्षरण, भूजल का स्तर बनाए रखने और जमीन की नमी बरकरार रखने वाली कई जोहड़ व नदियों को आसरा देती रही है। लिहाजा अदालत के आदेशों का पालन अनिवार्य करते हुए अरावली को हर हाल में बचाया जाना चाहिए।

**वैक्सीन की मिक्स-मैच रणनीति कारगर रही तो यह कई प्रकार से लाभकारी हो सकेगी**

संसाधन सीमित हों, मांग अधिक हो तो अच्छे-खासे गणित गड़बड़ जाते हैं। हमारे देश में ऐसा ही एक दृश्य कोरोना के टीकाकरण अभियान में नजर आ रहा है। हालांकि देश में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत इस साल के आरंभ के साथ हो गई थी लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर और फिर कई तरह की अव्यवस्थाओं ने वैक्सीनेशन की चाल में सुस्ती ल दी। इसी दौरान देश में कई जगह टीकाकरण केंद्र बंद होते हुए भी नजर आ रहे हैं। जब देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर आशंका कायम हो तो टीकाकरण के गरस्त में आ रही बाधाएं चिंता पैदा करती हैं।

यहां सवाल है कि इस चित्ता का हल क्या है। इसके कई जवाबों में से एक उत्तर यह है कि देश को कोरोना टीके का उत्पादन बढ़ाने, विदेश से वैक्सीनों का आयात करने के साथ-साथ टीकों के कॉकटेल या मिक्स-मैच नीति पर विचार करना चाहिए। टीकों के मिक्स-मैच या कहें कॉकटेल नीति यह है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी कंपनी का पहला टीका (डोज) लगाया गया है, उसे दूसरी खुराक किसी अन्य टीके की दी जा सकती है। इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के गांव औदी की कलां और एक अन्य गांव में मई के अखिरी हफ्ते में स्वास्थ्य टीम की लापरवाही की वजह से करीब 20 लोगों को पहली खुराक में कोविशिल्ड और दूसरी खुराक के रूप में कोवैक्सीन लगा दी गई हालांकि किसी ने साइड इफेक्ट की शिकायत नहीं की। उत्तर प्रदेश से पहले महाराष्ट्र के जालना जिले में भी ऐसा ही एक मामला आया था। वह 72 साल के एक बुजुर्ग दत्तात्रेय वाघमरे को दो अलग-अलग वैक्सीनों लगा दी गई थीं। अब देश के डॉक्टर गलती से हुए मिक्स-मैच वाले इस-

वैक्सीनों के कॉक्टेल  
का दूसरा बड़ा फायदा  
भारत जैसे ज्यादा आबादी  
वाले मुल्कों में टीकाकरण  
को रपतार देने में हो  
सकता है। यदि किसी  
जगह लोगों को पहले  
कोविशील्ड वैक्सीन दी जा  
चुकी है और उसकी दूसरी  
डोज फिलहाल उपलब्ध  
नहीं है तो उन्हें उपलब्ध  
कोवैक्सीन की दूसरी डोज  
दी जा सकती है, लेकिन  
निश्चय ही इसे केंद्र सरकार  
और मेडिकल एजेंसियां  
तय करेंगी। यह नहीं होना  
चाहिए कि लापरवाही या  
भूलवश किसी व्यक्ति को  
दो अलग वैक्सीनें लगा दी  
जाएं। कोविड-19 के  
खिलाफ बनीं वैक्सीनों को  
लेकर आम समझ यह है  
कि अंततः उन्हें इंसानों के  
शरीर में एंटीबॉडीज बनाते  
हुए इय्युनिटी पैदा करनी है,  
ताकि लोग कोरोना वायरस  
की चपेट में आने से बच  
सकें।



विदेश में हुए हैं। जर्मनी के जारलैंड  
यूनिवर्सिटी में में ऐसा एक शोध  
एस्ट्रोजेनेका और फाइजर नामक दो  
वैक्सीनों पर किया गया। शोध में  
साबित हुआ कि एक ही टीके की दो  
खुराक लेने के बजाय दो अलग-  
अलग वैक्सीनों से ज्यादा मजबूत  
इम्युनिटी हासिल की जा सकती है।  
इसमें शोधकर्ताओं ने पाया कि जेन  
लोगों को पहली खुराक एस्ट्रोजेनेका  
और दूसरी खुराक बायोएन्टर-कॉ  
फाइजर की मिली थी, उनमें ऐसे लोगों  
के मुकाबले ज्यादा इम्युनिटी मिली  
जिन्होंने दोनों खुराकों एक ही वैक्सीन  
की ली थीं।

उल्लेखनीय है कि यूरोपियन  
मेडिसिन एजेंसी से मंजूरी मिलने के  
बाद इस साल जनवरी में सभी जर्मन  
वयस्कों को एस्ट्रोजेनेका की वैक्सीन  
(कोविशील्ड) लगाई गई थी।  
हालांकि उस बीच कुछ युवतियों में  
वैक्सीन लगाने के बाद दिमाग में खून  
जमने की शिकायत हुई। इसे देखते  
हुए जर्मनी में अप्रैल में कोविशील्ड  
का इस्तेमाल 60 साल से ऊपर के  
लोगों तक ही सीमित रखने का

फैसला किया गया, लेकिन अध्ययन में वैक्सीनों के कॉकटेल फायदे देखते हुए पहली खु कोविशील्ड टीके की लेने वाले ल

नए न के राक तोगों शक्तिशाली प्रतिरक्षा प्रणाली हासिल हुई। जाहिर है कि दो वैक्सीनों के इस्तेल के बारे में निश्चय ही अभी कुछ सदैह बने हुए हैं। जैसे यह पूछा जा रहा है कि वैक्सीनों का कॉकटल कोवैक्सीन का निर्माण कोविड-19 के निष्क्रिय वायरस से हुआ है। ऐसे में अगर दोनों डोज में अलग-अलग वैक्सीन दी जाएंगी तो इससे वैक्सीन के असर में अंतर आ सकता है।

कोविड-19 के खिलाफ आखिर कितनी इम्युनिटी देता है। इस बारे में भारत में नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) डॉ. बीके पॉल ने कहा है कि वैज्ञानिक नजरिये से देखें तो ऐसा कासंभव है कि लोगों को वैक्सीन का कॉकटेल दिया जाए, लेकिन इस मुद्दे पर और शोध की जरूरत है। वैसे इन सवालों के जवाब जल्दी ही मिल सकते हैं, क्योंकि इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई शोधकार्य चल रहे हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने निष्कर्षों के आधार पर इस बारे में कोई परामर्श जारी कर सकता है।

बात चाहे कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक-बी, फाइजर या साइनोवैक की हो, इनमें से ज्यादातर की संरचना और कार्यप्रणाली एक दूसरे से अलग हैं। इसी वजह से आम लोगों के अलावा विज्ञानी भी संशय में हैं कि वैक्सीनों का कॉकटेल बाद में कहीं कोई बड़ी समस्या न पैदा कर दे। जैसे एक खतरा यह है कि वैक्सीन का कॉकटेल एक दूसरी वैक्सीन की प्रभाविकता को कम कर सकता है। दोनों डोज में वैक्सीन अलग-अलग होने से लोगों को वैक्सीन का बूस्टर डोज नहीं मिल पाएगा। ध्यान रहे कि एक ही वैक्सीन की दूसरी खुराक को बूस्टर डोज माना जाता है, जो कि शरीर में पहली डोज से बनी एटीबॉडीज को और मजबूत करने के लिए दी जाती है। इसके अलावा समस्या इसलिए भी हो सकती है, क्योंकि इन्हें बनाने की कार्यप्रणाली अलग है। मिसाल के तौर पर कोविशील्ड वैक्सीन को वायरस के प्रोटीन स्पाइक के आधार पर तैयार किया गया है। इसके विपरीत

यह प्रभाव सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी। जाहिर है कि अगर वैक्सीन का कॉकटेल कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है तो इसके कई फायदे हैं। जैसे पहला लाभ यह है कि इससे लोगों में एक ही वैक्सीन की दो खुराकें लेने के मुकाबले ज्यादा इम्युनिटी या एंटीबॉडीज हासिल हो सकती है। उल्लेखनीय है कि वैक्सीनों का असर इसी से नापा जाता है कि वैक्सीन लेने वाले व्यक्ति के शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ कितनी एंटीबॉडीज बनीं। साथ ही यह भी देखा जाता है कि ये एंटीबॉडीज कितनी असरदार हैं। इसी से पता चलता है कि वायरस को कोशिकाओं में जाने से रोकने में एंटीबॉडीज कितनी कारगर रहती हैं। वैक्सीनों के कॉकटेल का दूसरा बड़ा फायदा भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले मुल्कों में टीकाकरण को फ्रप्तर देने में हो सकता है। यदि किसी जगह लोगों का पहले कोविशील्ड वैक्सीन दी जा चुकी है और उसकी दूसरी डोज फिलहाल उपलब्ध नहीं है तो उहें उपलब्ध कोवैक्सीन की दूसरी डोज दी जा सकती है, लेकिन निश्चय ही इसे केंद्र सरकार और मेडिकल एजेसियं तय करेंगी। यह नहीं होना चाहिए कि लापतवाही या भूलवश किसी व्यक्ति को दो अलग वैक्सीनें लगा दी जाएं। कोविड-19 के खिलाफ बनी वैक्सीनों को लेकर आम समझ यह है कि अंततः उन्हें इसानों के शरीर में एंटीबॉडीज बनाते हुए इम्युनिटी पैदा करनी है, ताकि लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकें।

आधुनिक अध्ययन में अभी ऐसी कोई प्रणाली व्यवस्था विकसित नहीं हुई जो जंगल का मोल नाप सके

आधुनिक अध्ययन और शोध आदि  
अभी ऐसी कोई प्रणाली या व्यवस्था  
वकसित नहीं हुई है जो जंगल का  
गोल नाप सके। सच तो यह है कि  
इस करने की इंसान की हैसियत भी  
हीं। कहां वे गव से खड़े ललहाते  
बुशबू, खुशी, आनंद, उल्लास, उमंग  
और जीवन बिखेरते, सांसों का दान  
कर, जहर लीलते, हरे भरे मुस्कराते  
तियाते, जीवन पर्यट देते रहने का  
पंकल्प लिए ये जंगल और कहां ये  
गरुर, खुदगर्ज, लालची, हिंसक,  
जहर उगलता और विनाश को आमादा  
सान। इन अनमोल जंगलों को  
जाड़कर बस्ती बसाना, फैक्टरी



मनुष्य की वीभत्स मनोवैज्ञानिक समझ कहें या कुछ और नाम दे सकते हैं। लालच और जरूरत के बीच के खेल ने लालच को हिंसक बना दिया। जहर (कार्बन डाइऑक्साइड) सोखने वाले जंगल हमें जीवन का अमृत देते हैं, पर हम विनाश पर आमादा हैं। दुनिया भर में हजारों ऐसे प्रमाण उपलब्ध हैं कि जब जब जंगल उड़े, तब तब आपदाओं का आगमन हुआ है। अमेजन, आस्ट्रेलिया, टेकोमा (अमेरिका) और भारत में उत्तराखण्ड सहित जंगलों के विनाश या आग लगने के बाद हमने आपदाओं को देखा है। आस्ट्रेलिया में हजारों प्रजातियों के करोड़ों जीव-जंतु-पौधे गायब हो गए। उत्तराखण्ड में जंगल की बर्बादी, नदियों की धारा में बाधाएं और तमाम परिवेजनाओं के बाद भीषण आपदाओं और उनसे पैदा विनाश को देखा गया है। आपदाओं का क्रम निरंतर जारी है। विकास के नाम पर या व्यवसाय के नाम पर जंगल ही सदैव

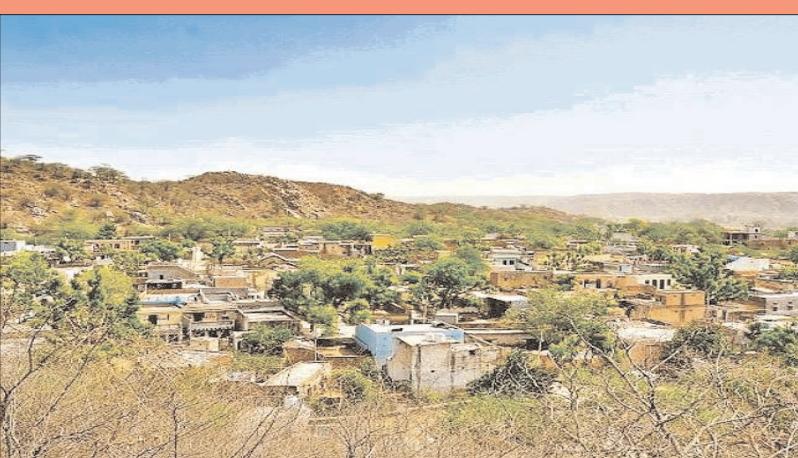
है। स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा पर उसे ऐसा संकट कई पीढ़ियों ने नहीं देखा हो भयावह संकट की तह में प्रकृति का विश्व है। जंगलों में लाखों वर्षों से अनेक वायरल बैक्टीरिया रहते हैं, वहीं उनके प्राकृतिक हैं। जंगल उजड़े तो उनके रहवास विखंडल वे बाहर आकर अचानक विनाशक हो जायरसों का यह विस्फोट शोध के लिए अध्ययन के लिए है या वैश्विक व्यापार या सर्वोच्च होने की सनक का परिणाम विनाशकारी शरारत है? ये सभी सवाल भी जिंदा हैं। इस बात को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए कि किसी भी व्यवस्था, सरकारी विचारधारा, लालच, पार्टी, व्यक्ति, धर्म या भाषा, क्षेत्र या व्यवसाय की जिद से देश है। देश के व्यापक हित बड़े हैं। स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन सर्वोच्च है। कोई भी अगतिविधि रास्ते के लिए अहितकर है और तत्काल रोकना हमारा दायित्व है।

सरकार दे मुआवजा

के नतीजों ने निश्चित रूप से विपक्षी खेमे का हासला बढ़ाया है। उसे 2024 लोकसभा चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी और एनडीए को हराने का लक्ष्य अब पहले जैसा नामुमकिन नहीं लग रहा। लेकिन आम चुनाव से पहले यूपी विधानसभा चुनाव में खासी जांच-आजमाइश होगी। ऐसे में वे तमाम ताकतें जो बीजेपी को सत्ता से बाहर देखना चाहती हैं, अगर आपस में संवाद और समन्वय के स्रुत्र मजबूत कर रही हैं तो यह आश्वर्य की कोई बात भले न हो, महत्वपूर्ण जरूर है। अक्सर ऐसे छोटे-छोटे प्रयासों का बड़ा नतीजा निकलता है। दिक्कत बस यह है कि विपक्ष की एकजुटता या उनमें समन्वय का लक्ष्य महज बातचीत से हासिल नहीं होने वाला। इस प्रक्रिया में शामिल तमाम छोटी-छोटी पारिंटां और नेता अपनी-अपनी राजनीतिक जमीन का विस्तार करने का मकसद भी साथ लिए चल रहे हैं, जो मौजूदा हालात में आम तौर पर कांग्रेस की कीमत पर ही संभव है। जाहिर है, कांग्रेस स्वेच्छा से तो इसे मंजूर नहीं कर सकती। ऐसे में स्पष्ट है कि बातचीत, विचार-विमर्श और मेलजोल के बीच आपस में शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया भी चलती रही। % तुम्हीं से दोस्ती और तुम्हीं से लड़ाई% की मौजूदा मजबूरी का ही नतीजा है कि कांग्रेस को साथ न रखते हुए भी साथ बताया जाए और कांग्रेस अलग रहते हुए भी खुद को अलग न लताया। बहुद्वाल इन्हीं

दिल्ली समेत देश के अन्य कई क्षेत्रों को रेगिस्तान बनने से बचाने में अरावली पर्वत की अहम भूमिका

पिछले सप्ताह उच्चतम न्यायालय के एक अदेश के बाद फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में सूरजकुंड से सटे खोरी गांव की करीब 60 हजार आबादी चिंता में है। मानवीय नजरिए से भले ही यह बहुत मार्मिक लगे कि एक झटके में 80 एकड़ में फैले शहरी गांव के करीब दस हजार मकान तोड़े जाने हैं, लेकिन यह भी कड़वा सच है कि राजस्थान के बड़े हिस्से, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब को सदियों से रेगिस्तान बनने से रोकने वाले अरावली पर्वत को बचाने को यदि अदालत सख्त नहीं हो तो नेता-अफसर और जमीन माफिया अब तक समूचे पहाड़ को ही चट कर गया होता। कैसी विडंबना है कि जिस पहाड़ के कारण हजारों किमी में भारत का अस्तित्व बचा हुआ है, उसे बचाने के लिए अदालत को बार-बार आदेश देने होते हैं। वर्ष 2016 में ही पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट अरावली पर अवैध कब्जा कर बनाई गई कालोनियों को ध्वस्त करने के आदेश दे चुका था, उसके बाद फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश पर मोहर लगाई थी।



सके बाद 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने इको अस्टिटिव क्षेत्र में सभी प्रमुख और मामूली खनन एवं पूरी तरह रोक लगा दी थी। जान लें कि दिल्ली, दिल्ली रियाया व राजस्थान का अस्टिटिव ही अरावली एवं गढ़वाली क्षेत्र टिका है और यदि इससे जुड़े संरक्षण के नानूतों में थोड़ी भी ढील दी गई तो भले ही उक्त क्षेत्र रकारी खाजाने में कुछ धन आ जाए, लेकिन जारों हेक्टेयर का कृषि और हरियाली क्षेत्र गेस्टस्तान में बदल जाएगा। यह भी याद करना चाहिए कि यह अस्टिटिव रुरी है कि वर्ष 2019 के 27 फरवरी को दिल्ली रियाया विधानसभा में जो हुआ था उसने अरावली के प्रति सरकारों की संवेदनहीनता को दाहिर कर दी थी। बहाना था कि महानगरों का विकास करना है, इसलिए लाखों वर्ष पुरानी ऐसी जगहों पर चना जो कि रेगिस्ट्रान के विस्तार को रोकने से लेकर जैवविविधता संरक्षण तक के लिए अनिवार्य है, उसे कंट्रीट का जंगल बनने के लिए छोड़ दिया गया।

बीते दिनों हरियाया विधानसभा ने सबधित एकट में ऐसा बदलाव किया कि अरावली पर्वतमाला की लगभग 60 हजार एकड़ जमीन शहरीकरण के लिए मुक्त कर दी गई। इसमें 16,930 एकड़ गुरुग्राम में और 10,445 एकड़ जमीन फरीदाबाद में आती है। अरावली की जमीन पर बिल्डरों की शुरू से ही गिर्द दृष्टि रहती है। हालांकि एक मार्च को पंजाब भूमि संरक्षण (हरियाया संशोधन) अधिनियम-2019 पालायर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए हरियाया विधानसभा के प्रस्ताव के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने

सरकार को चौ  
छेड़छाड़ हुई  
अरावली का  
बचा है। राज  
अवैध खनन  
दिखती है।

वेता दिया था कि यदि अरावली से तो खेर नहीं। ऐसा लगता है कि अस्तित्व अदालत के बदौलत ही स्थान सरकार भी अरावली क्षेत्र में रोकने को लेकर अदालत में बचती

अरावली पर्वतमाला को दुनिया के सबसे प्राचीन पहाड़ों में गिना गया है।

ऐसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संरचना का बड़ा हिस्सा बीते चार दशकों में पूरी तरह न केवल नदारद हुआ, बल्कि कई जगह गहरी खाइ हो गई। अरावली की प्राकृतिक संरचना नष्ट होने की ही

पर्यावरण कार्यक्रम की एक रिपोर्ट दुनिया के लगभग 100 देशों में जीमान रेत के ढेर से ढक रही है। कि यह खतरा पहले से रोगस्तान से इतर है। धीमी गति से विस्तार पा का सबसे ज्यादा असर एशिया में ही गी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के शोध बताता है कि थार रोगस्तान से बाहर निकल कर कई राज्यों में जरूरतवाला पा प्रौद्योगिक लखरा नहीं पाया है त्रसदी है कि वहाँ से गुजरने वाली साहिबी, कृष्णावति, दोहन जैसी नदियाँ लुम् हो रही हैं। विश्व वन्य संस्थान की एक रिपोर्ट बताती है कि 1980 में अरावली क्षेत्र के 247 वर्ग किमी पर आबादी थी, आज यह 638 वर्ग किमी हो गई है। इसके 47 वर्ग किमी क्षेत्र में कारखाने भी हैं। वैसे तो भूमाफिया की नजर दक्षिण हरियाणा की पूरी अरावली पर्वत श्रेणी पर है, लेकिन सबसे अधिक नजर गुरुग्राम, फरीदाबाद एवं नूबू इलाके पर है।

है। वर बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि स्थान से सूदूर पाकिस्तान व उससे नीचे भीषण रेगिस्तान से हर दिन लाखों लोग हैं और यह हरियाली वाले इलाकों के बीचे इसकी सुरक्षा का काम अरावली के नदियों से करती रही है। विडंबना है जो दशकों में यहां मानवीय हस्तक्षेप तना बढ़ा कि कई स्थानों पर पहाड़ों पर खाई हो गई और एक बड़ा कारण यह है कि अब उपजाऊ जमीन पर रेत की तरार हो रहा है। खेड़े से आरंभ होकर करीब 692 फैली अरावली पर्वतमाला का केंद्र सबसे ताकतवर स्थान रायसीना गढ़ है जहां ग्राफ्टिं भवन स्थित है।







# प्रभास ने ठुकराया करोड़ों का एट

जहां एक और कई कलाकर ऐसे हैं जो पैसे की खातिर गुटखा और शराब का विज्ञापन करने में भी नहीं हिचकते जिससे की उनके करोड़ों फैंस के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है, वहीं बाहुबली प्रभास जैसे सुपरस्टार भी हैं जो करोड़ों के विज्ञापन को लात मारने में देर नहीं लगाते। भारत में प्रभास लोकप्रिय नाम है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक उनके फैंस हैं। ऐसे में विज्ञापन कंपनियां उन पर दांव लगाना चाहती हैं। उन्हें अपना ब्रैंड एम्बेसेडर बनाना चाहती हैं। खबर है कि पिछले एक साल में प्रभास को 150 करोड़ रुपए से ज्यादा के ब्रांड एंडोर्समेंट ऑफर मिले, लेकिन प्रभास ने सभी को रिजेक्ट कर दिया। इसके पीछे प्रभास का मानना है कि वे अपने फैंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वे ऐसी किसी चीज का विज्ञापन नहीं करना चाहते जिसके इस्तेमाल में वे खुद कंफर्टबल महसूस ना करते हों। ऐसा नहीं है कि वे विज्ञापन नहीं करेंगे। लेकिन उन्हीं वस्तुओं का विज्ञापन करेंगे जिसे वे पसंद करते हों। उन्हें पता है कि वे किसी चीज का विज्ञापन करेंगे तो उनके फैंस बिना सोचे समझे फौरन उसका इस्तेमाल शुरू कर देंगे।

**करिंमा कपूर ने जब  
किया था अपने पति के  
कारनामों का भंडाफोड़**

करिश्मा कपूर की वैवाहिक जीवन बहुत खराब रहा। पति संजय कपूर से उनके रिश्ते इतने खराब हो गए कि करिश्मा ने उनके बारे में सार्वजनिक रूप से भला-बुरा कहा। इस रिश्ते को उन्होंने संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। आखिरकार तलाक लेकर उन्होंने इस रिश्ते से मुक्ति पाई। आइए जानते हैं तब उन्होंने अपने पति के बारे में क्या-क्या कहा था।

- करिश्मा के अनुसार उनके 4 महीने की बेटे के तबियत खराब थी, जिसके कारण वह पति के साथ यूके ट्रिप पर नहीं जा सकी। इससे संजय बेहद नाराज हुए और अकेले ही चले गए। बाद में करिश्मा यूके पहुँची तो संजय रात-रात भर गायब रहते थे। उन्हें अपने बेटे की तबियत से कोई लेना-देना नहीं था। उनके लिए गोल्फ खेलना ज्यादा महत्वपूर्ण था।

-हनमून क दारान हा  
करिश्मा के सामने संजय

अपने भाई के साथ यह  
चर्चा कर रहे थे कि  
करिश्मा कितने पैसे ला  
सकती हैं। इससे करिश्मा  
नहीं उड़ पाई।

-एक बार संजय ने करिश्मा  
से अपनी मां द्वारा दी गई

द्रेस पहनने को कहा।  
चूंकि करिश्मा प्रेग्नेंट थीं  
इसलिए वह ड्रेस उन्हें फिट  
नहीं हो रही थी। यह देख  
संजय बेहद नाराज हो  
गए। उन्हें अपनी सांस ले

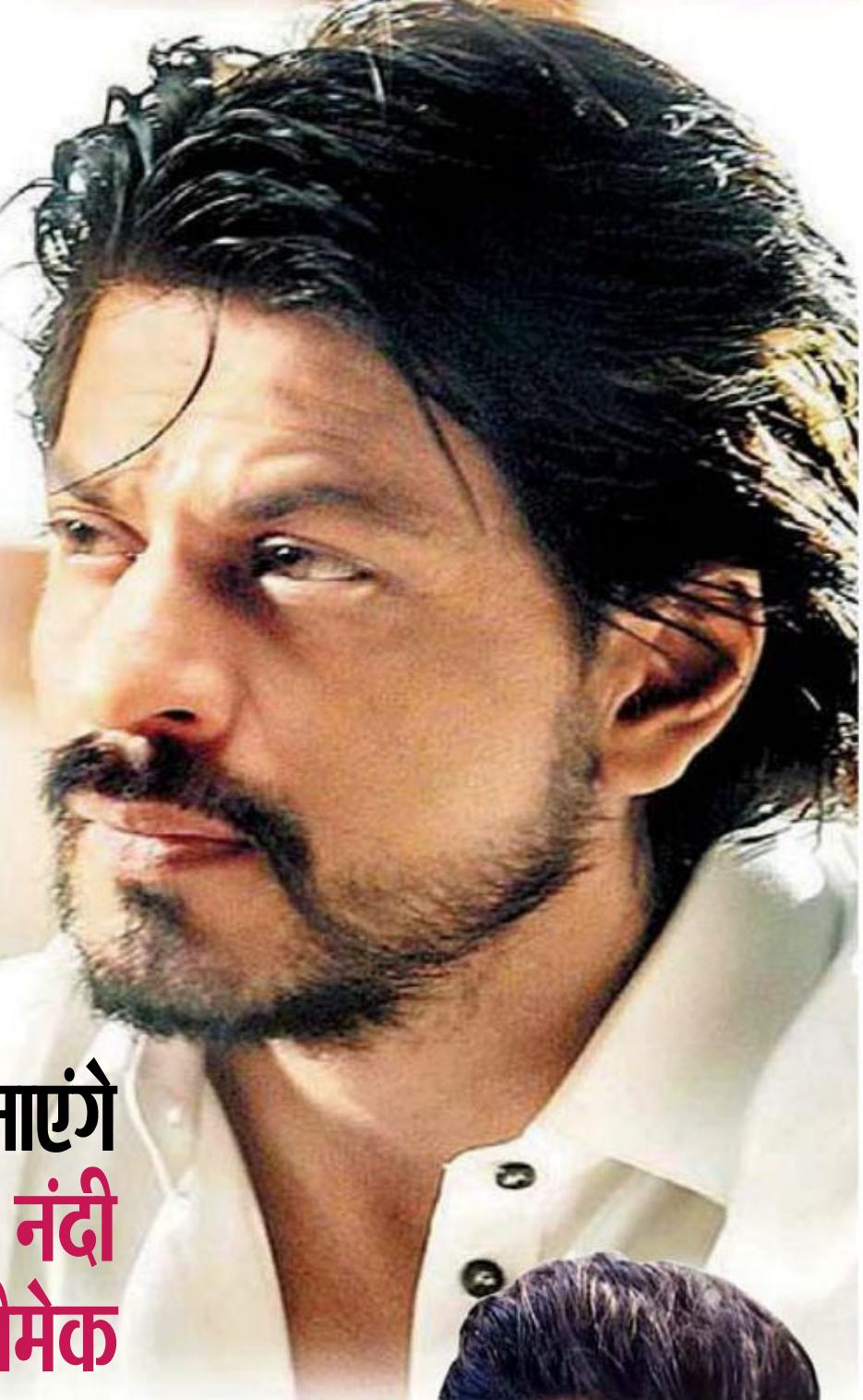
गए। उन्हाने अपनो मा को करिशमा को थप्पड़ लगाने के लिए कहा। -संजय अक्सर करिशमा से दुर्घट्यहार करते थे। मारपीट भी करते थे। चोट के निशान करिशमा मेकअप के सहारे छिपाती

थी। संजय की मां की इसमें मौन स्वीकृति थी।  
-करिश्मा के अनुसार वे अपने पति के लिए महज एक ट्रॉफी थीं और यह शादी उनके लिए ट्रॉफी जीतने समान था।

- शादी के पहले भी संजय ने करिश्मा की माँ बबीता से बदतमीजी की ? थी। इससे करिश्मा ने शादी नहीं करने का निर्णय ले लिया था, लेकिन बाद में उन्हें मना लिया गया।
- रणधीर कपूर इस शादी से कभी खुश नहीं थे। रणधीर के अनुसार उनका दामाद कितना अद्याश है ये बात पूरी दिली जानती है।



**शाहरुख खान** को आज बॉलीवुड में 29 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनकी पहली रिलीज 'दीवाना' 25 जून 1992 को रिलीज हुई थी। इस मौके पर शाहरुख ने अपने फैंस का शुक्रिया अदा किया है। इस खास दिन को शाहरुख शूटिंग करते हुए मना रहे हैं। शाहरुख ने मुंबई में यशराज फिल्म्स स्टूडियो में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान की शूटिंग फिर से शुरू कर दी है। पठान के सेट के बाहर सुपरस्टार कार देखी गई। कोरोना की दूसरी लहर के कमजोर होते ही लॉकडाउन में ढील दी गई और उसके बाद पठान ने अपना शूटिंग शेड्यूल फिर से शुरू कर दिया है। अभी केवल किंग खान शूटिंग कर रहे हैं। जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण अगले कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग इस शेड्यूल में की जाएगी। इसके बाद टीम एक्शन और बड़े पैमाने पर दृश्यों की शूटिंग के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर पहुंचेगी। पठान का निर्माण आदित्य चौपड़ा कर रहे हैं। आदित्य कई बड़ी फिल्मों पर काम कर रहे हैं। इनमें सलमान खान की टाइगर 3, जुनैद खान की पहली महाराज, सैफ अली खान, रानी मुखर्जी, सिद्धांत चतुर्वेदी की बंटी और बबली 2, विक्की कौशल की अगली मूवी, रणवीर सिंह की जयेशभाई जोरदार, रणवीर कपूर की शमशेरा जैसी फिल्में हैं। इनमें से कुछ रिलीज के लिए तैयार हैं।



# अजय देवगन बनाएंगे तेलुगु हिट नंदी का हिंदी रीमेक

अजय देवगन इन दिनों एकिटिंग के साथ-साथ बौद्धि प्रोड्यूसर भी व्यस्त हैं और कई फ़िल्मों पर काम कर रहे हैं। अजय और वी. वेंकट रमना रेण्टी उर्फ दिल राजू पहली बार एक जबरदस्त कहानी को सामने लाने के लिए साथ आ रहे हैं। दो दिग्गजों ने फ़िल्म के हिंदी रीमेक के लिए 2021 की तेलुग हिट मूवी नंदी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। नंदी एक क्राइम कोर्ट रुम ड्रामा है। इस फ़िल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों ने एक साथ पसंद कर सफल बनाया था। निर्माता अजय देवगन कहते हैं, 'नंदी एक महत्वपूर्ण फ़िल्म है, जो प्रशासन में कुछ खामियों को उजागर करती है। दिल राजू और मैंने ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इस फ़िल्म का हिंदी में रीमेक बनाने के लिए हाथ मिलाने का फैसला किया है। स्क्रिप्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।' निर्माता दिल राजू ने कहा, 'नंदी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनी? फ़िल्म है और हम इस कहानी को हिंदी भाषी दर्शकों तक ले जाने के लिए उत्सुक हैं। मैं इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर अजय देवगन के साथ जुड़ कर बहुत खुश हूं। फ़िल्म के बाकी डिटेल्स जल्दी ही साझा करेंगे।' स्क्रिप्ट फाइनल होते ही कलाकारों का चयन होगा और जल्दी ही इस बारे में घोषणा की जाएगी।



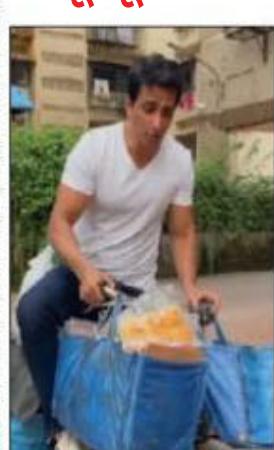
# सत्यनारायण की कथा में कार्तिक की हीरोइन हो गई फाइनल!

वाले दिनों में इस बात की घोषणा होगी। श्रृंखला और कार्तिक पहली बार साथ काम करेंगे। उनकी जोड़ी में ताजगी नजर आएगी। हालांकि यह मुख्य रूप से कार्तिक की कहानी है, लेकिन श्रद्धा का रोल भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।' 'श्रद्धा और कार्तिक को साथ में पहली बार लाने की कोशिश निर्माता दिनेश विजन ने की थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। एक और फ़िल्म का ऑफर दोनों को मिला था, तब भी बात नहीं बनी थी। शायद इस बार यह जोड़ी जम जाए।



**खतरों के खिलाड़ी : श्वेता तिवारी, अर्जुन? बिजलानी सहित ये हैं टॉप 5 फाइनलिस्ट!**

खतरों के खिलाड़ी 11 की शूटिंग भले ही विदेश में हो रही थी, लेकिन भारत में इसके लगातार चर्चे हो रहे हैं। रोहित शेट्टी द्वारा होस्ट किया गया यह शो अब टेलीविजन प्रीमियर के लिए तैयार है। रोहित शेट्टी और सारे प्रतियोगी भारत लौट आए हैं। कुछ रिपोर्ट्स से पता चला है कि टॉप 5 फाइनलिस्ट में किसने जगह बनाई है। दिव्यांका त्रिपाठी, वरुण सूद, श्वेता तिवारी, अर्जुन बिजलानी और आदित्य सिंह के बारे में कहा जा रहा है कि ये पांचों अंतिम दौड़ में घुट्ठे हैं। हालांकि फाइनल टास्क हो चुका है, लेकिन विजेता का नाम एक लाइव इवेंट में बताया जाएगा। इस बार कई नामी लोग इस शो में नजर आएंगे। इन पांचों के अलावा राहुल वैद्य, निष्ठा तंबोली, आस्था गिल, सना मकबुल, सौरभ राज जैन, महक चहल और अनुष्ठा सेन भी प्रतियोगी के रूप में शामिल हए हैं। अब इस शो के टीवी पर प्रसारित होने का इंतजार है।



लोगों की मदद करने के साथ-साथ सोनू सूद सोशल मीडिया पर मजेदार पोस्ट करते रहते हैं। कभी वे ढाबा खोल लेते हैं तो कभी चाकू-छुरी की धार तेज़ करते नजर आते हैं। अब सोनू ने एक वीडियो डाला है जिसमें वे ब्रेड और अंडे बेचने की बात करते नजर आ रहे हैं। इसे उन्होंने सोनू सूद की सुपरमार्केट नाम दिया है। एक साइकिल पर उन्होंने बहुत सारा सामान लाद रखा है। कई झोले टंगे हैं जिनमें ब्रेड है। पीछे अंडे की कैरेट है। सोनू इसे सुपर मार्केट कहते हैं और अंडा 6 रुपये और ब्रेड का दाम 40 रुपये बताते हैं। और भी कई सामान उनके झोले में नजर आता है। कोरोना काल में सोनू सूद मसीहा बन कर उभरे हैं और उन्होंने हजारों लोगों की मदद की है जिसके कारण वे लोकप्रियता में कई दिग्गजों से आगे निकल गए हैं।

